





# पलामू में शराब पीने वालों ने बनाया शराब उपभोक्ता संघ

नवीन मेल संवाददाता  
मेदिनीनगर। पलामू में शराब उपभोक्ता संघ  
का गठन किया गया है। इस संघ में कई  
जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और बड़े  
चेहरे शामिल हैं। शराब उपभोक्ता संघ के  
कार्यकारी सचिव गुड़ा पाठेय ने बताया कि  
मेदिनीनगर के निजी होटल में रविवार को संघ  
की बड़ी बैठक होगी, जिसमें कार्यकारिणी का  
गठन किया जाएगा। ये संघ प्रिंट रेट से  
अधिक कीमत पर बिकने वाली शराब का  
विरोध करेगा, साथ ही साथ मामले में  
पीआईएल की भी योजना तैयार करेगा।  
इसके अलावा प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर  
बिकने वाली शराब का एक ब्यौरा तैयार कर-



के, प्रवर्तन निदेशालय को इससे होने वाली अवैध कर्माई की जानकारी संघ की ओर से दी जाएगी। दरअसल पलामू में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बिक रही है। कई मौकों पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है। एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने के मामले में पलामू में अब तक दो एफआईआर हो चुके हैं जबकि दो लोगों को गोली मारी गई है। पलामू में शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से 20 से 50 अधिक कीमत पर बेची जा रही है। प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर बिक रहे शराब के कारण नाराज लोगों ने शराब उपभोक्ता संघ का गठन किया है।

# कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने वसीम अकरम

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। शहर के पुलिस लाइन में शुक्रवार को ज्ञारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ, शाखा पलामू जिला बल की तुतीय शाखा चुनाव संपन्न हुआ। जिसमें ज्ञारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों ने सर्वसमर्पित से अध्यक्ष पद पर वसीम अकरम को चुना। इसके बाद सभी सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष वसीम अकरम को फूल का माला पहना कर उनका भव्य स्वागत किया गया और संघ के लिए बेहतर कार्य करने की कामना की। वहीं मौके पर उपस्थित वसीम अकरम ने कहा कि जिस निष्ठा भाव

से लोगों ने हमें अध्यक्ष पद पर चुना है हम उस पर खरा उतरेंगे। हम अपने संघ के लोगों के लिए हमेशा सुख दुख में खड़ा रहेंगे। वही उपाध्यक्ष पद पर दिलीप कुमार, मंत्री पद पर मनोज राम, कोषाध्यक्ष पद पर रामायारी देवी, संयुक्त मंत्री पद पर पिंकी देवी, संगठन मंत्री पद पर मनोज कुमार पासवान, मुख्यालय प्रतिनिधि पद पर अशोक महतो चुना गया। चुनाव के समय मौके पर पुलिस में से ऐसोशिएशन के शाखा अध्यक्ष अक्षय पासवान मुख्य रूप से उपस्थित थे। इनके अलावा पलामू जिला बल के अन्य पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी भी उपस्थित थे।

NEWS इन ब्रीफ

**बाइक की चोरी, शहर  
थाना में दिया गया  
आवेदन**

मादनानगर। शहर थाना क्षत्र  
के कच्चहरी व्यवहार न्यायालय  
के सामने से जेएच 03 जेड  
9978 बाइक की चोरी हो गई।  
बाइक मालिक अरविंद सिंह ने  
शहर थाना में आवेदन दिया  
है। दिए गए आवेदन के  
अन्तर्गत आवाहन देखिये।

अनुसार शुक्रवार के दिन में  
व्यवहार न्यायालय के गेट के  
पास अपनी स्लैटर प्लस  
बाइक लगाकर अंदर गए थे  
काम होने के बाद बाहर आए  
तो बाइक गायब थी। उन्होंने  
अपने स्तर से खोजने का हर  
संभव प्रयास किया पर कुछ  
पता नहीं चला। बाद में शहर  
थाना में बाइक चोरी का  
आवेदन देते हुए मामला दर्ज  
कराया।

# बाइक का भव्य लॉच समारोह आज

मेदिनीनगर। रविवार को साइन मोटरसाइकिल को लॉच करने का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से हारिजन होटल के शो रूम में आयोजित है। जिसकी टेस्ट राइड की सुविधा भी मौके पर उपलब्ध रहेगी। ये शो रूम मेदिनीनगर, रेडमा, राँची रोड में राष्ट्रीय नवान मेल, समाचार पत्र के कार्यालय के पास अवस्थित है। नई मोटरसाइकिल के चाहने वाले के लिए ये एक सुनहरा मौका है।

**झारखण्ड मुक्ति मोर्चा  
व्यापार प्रकोष्ठ पलामू  
जिला के अध्यक्ष का  
स्वागत**

मेदिनीनगर। आज बाजार क्षेत्र में व्यवसाई भाइयों के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के व्यपार प्रकोप पलामू जिला के अध्यक्ष बनाये जाने पर मधुबनी खादी धंडार मिश्रा कोम्प्लेस से दीपू चौरसिया और उनकी टीम सचिव श्री मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष दीपेश भगत जिमी उपाध्यक्ष शाकिब सिद्धिकी और कोषा अध्यक्ष श्री राहुल कुमार सभी को माला पहना कर और बुके देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष दीपू चौरसिया ने कहा की मैं और हमारी टीम सभी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हर व्यवसाई भाइयों के हर सुख दुःख मे मैं और मेरी पूरी टीम दूकानदार भाइयों के सेवा मे हमेसा तत्पर रहेंगे सम्मानित करने वाले व्यवसाय भाइयों मे सरजू प्रसाद अग्रवाल जी, विष्णुदत्त मिश्रा, अरुण गुप्ता, पंकज शर्मा, डल्लू खान, कमल जयसवाल, राजेश भगत, लड्ढु खान, गौतम गुप्ता, कमल मुरारका सभी व्यवसायी

अधिकार

**गांगद ने बाहर से किया घर-घर जनसमार्क**

देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री का करें समर्थन : वीडी राम

सांसद बीड़ी राम ने लोगों को मो० नंबर  
90909024 पर मिस्ड कॉल कर मोदी  
सरकार को समर्थन देने का भी आग्रह  
किया

## कथा

**मेदिनीनगर।** भाजपा को आगामी लोक सभा चुनाव 2024 में आशीर्वाद एवं जनसमर्थन के लिए पलामू में पार्टी द्वारा घर -घर जनसम्पर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ सांसद बूथवार घर घर जाकर लोगों से समर्थन कि अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आज शहरी क्षेत्र के पलामू कलब बूथ संख्या 205, 206, 207 के शिवाजी मैदान रोड में महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम को लेकर भाजपाइयों की टोली दीपू सिंधानिया, संजय सिंधानिया, सुरेश जैन, पवन जैन, प्रो० अमल कुमार पांडे, रणविजय कुमार, डा०रघुवंश नारायण सिंह, अरुणजय नारायण सिन्हा समेत अन्य



आशीर्वाद एवं समर्थन मांगा इस दौरान भाजपा के सरकार के 9 साल की उपलब्धि एवं अपने कार्यकाल

लोगों को दिया। इतना ही नहीं सांसद ने मतदाताओं के आवास पर मोदी सरकार के बेमिसाल 9 साल का स्टीकर लगाते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि तभी देश के हर क्षेत्र में हो रहे विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को समय पर तेज गति से पूरा किया जा सकेगा। सांसद बीड़ी राम ने लोगों के मौम० नंबर 90909024 पर मिस्ट कॉल कर मोदी सरकार को समर्थन देने का भी आग्रह किया जनसंपर्क भ्रमण टोली में जिलाध्यक्ष विजयाननद पाठक, वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे, परशुराम ओझा, महा जनसंपर्क अभियान संयोजक विभाकर नारायण पांडे सहसंयोजक अविनाश वर्मा, विजय ओझा, जय दुबे, शिवकुमार मिश्रा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी सोमेश सिंह, नगरमंडल अध्यक्ष अविनाश उर्फ छोटू सिन्हा, संजय कुमार, नंदलाल गुप्ता उर्फ ठनठन, संजय गुप्ता अलख दुबे, मनोरंजन दुबे व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह जानकारी पलामू भाजपा के

## कांग्रेस कमेटी के विंग एवं डिपार्टमेन्ट के अधिकारों — विभाग संघ

# क अध्यक्षा का विचार मर्यादन

सभागार में पलामू जिला काग्रेस कमटा के तत्वधान में जिला अध्यक्ष जश रंजन पाठक उर्फ बिदू पाठक के अध्यक्षता में काग्रेस कमेटी के सभी विंग एवं डिपार्टमेंट के अध्यक्षों के साथ लक्ष्य 2024 को लेकर विचार मंथन किया गया। बैठक में सभी विंग के उपरित्थ अध्यक्षों ने अपने संगठन को लेकर बात रखें। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्री बिदू पाठक ने कहा कि लक्ष्य 2024 को प्राप्ति के लिए सभी विंग के प्रखण्ड अध्यक्ष एवं पंचायत को सशक्त और मजबूत होने की जरूरत है। आगामी 2 अक्टूबर से अभी सभी विंगों में ऐसी अपर्याप्त विधि लायी जाएगी जैसा कि विंगों

3 जुलाई से सभी प्रखंडों में बैठक आर कायक्रम तय कर्या गया है। जिसमें सभी विंग के पदाधिकारियों को उपस्थिति जरूरी है। ऐसी जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की नाकामी को बताए जाएगा। आज हम सभी लोगों को संकल्प लेकर लक्ष्य 2024 का प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे बैठक में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय प्रभारी जितेंद्र कमलापुरी कोषाध्यक्ष अजय साहू जिला उपाध्यक्ष विद्या सिंह चेरो सदर 20 सूत्री उपाध्यक्ष रामानंद पाठक रविंद्र कुमार महिला कमेटी के जिलाध्यक्ष इंटु भगत युवा के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक पासवान आदिवासी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जरूर उरांवङ्टक के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह युवा इंटक जिला अध्यक्ष शशांक सुमन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष अमृक प्रियदर्शी कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मत्थ्य विभाग के अध्यक्ष छोटू चौधरी जवाहर बाल मंच के जिला अध्यक्ष राज किशोर सिंह स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार दबे चंपा देवी सोशल मीडिया के अजय पांडे आदि लोग उपस्थित थे।



# उपायुक्त ने दुध संग्रहण एवं शीतल केंद्र का लिया जायजा

नवीन मेल संवाददाता। लातेहार उपायुक्त भोज सिंह वादव ने चंदवा प्रखंड अंतर्गत स्थित बनहरदी दुध उत्पादक प्राथमिक सहयोग समिति लिमिटेड में दुध संग्रहण एवं शीतलक केंद्र को निरीयण कर हो रहे कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने दुध की गुणवत्ता को जांच कर, विधि व्यवस्था से अवगत हुए। उपायुक्त ने दुध संघ से जुड़े किसानों के बारे में जानकारी ली। उहोंने किसानों को किए जाने वाले भूगतन तथा नियमित रूप से प्राप्त होने वाले दुध की मात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए



आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त को दुध की खरीद बिक्री

में जेएमएफ प्रबंधन की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए

विताया गया कि बनहरदी दूध संग्रह केंद्र में जेएमएफ किसान द्वारा दूध की खरीदारी करती है एवं महीने में 3 बार दूध का भुगतान किसान खाते में करती है। 1 से 10 तक का कुल दूध का भुगतान 15 तारीख तक। 11 से 20 तक का भुगतान 25 तारीख तक एवं 21 से 30 तक का भुगतान 5 तारीख तक किसानों के खाते में जाती है। इस दौरान उपायुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालक दुशास्त्र पशुओं को विटामिन मिनरल सहित समुचित पोषण का खाल करें, तो कम खर्च में अधिक दूध का उत्पादन कर सकते हैं।

पशुपालक अच्छी नस्ल की गाय एवं भैंस की प्रजाति पर ध्यान दें। पशु पालक दूध का अधिक उत्पादन के लिए पशुओं की संख्या बढ़ाने से ज्यादा पशुओं की पोषण पर ध्यान दें। गाय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गाय को हरा चारा खिलाए। आगे उहोंने कहा कि दुशास्त्र पशुओं के पोषण के लिए सुविधात्व विटामिन केलसियम एवं मिनरल दें। साथ ही गव्ह विकास विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं उन्होंने बतायी थीं। उपायुक्त ने जिला पशुपालन विभागीय कार्यालय की योजना है। आगे उहोंने कहा कि गाय के अच्छे स्वास्थ्य एवं ज्यादा दुध उत्पादन के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए।

## भू-माफियाओं और अंचल कर्मियों का कारनामा

# फर्जी दस्तावेज से बेच दी जमीन

आदिवासी की जमीन का फर्जीवांडा कर गैर  
आदिवासी को बेच डाला।

दाखिल खारिज कर  
मालगुजारी रसीद भी  
निर्गत कर दिया गया।

मामला चंदवा के वर्तमान  
मुखिया रंजीत उरांव के  
पूर्वज के नाम खतियानी  
जमीन का है।

क्या कहते हैं वर्तमान मुखिया सह रैयत रंजीत उरांव यहां भू-माफियाओं और अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभात से हमारे पूर्वजों की पुश्तेनी जमीन को बैठे विजित रही तो समान्य जमीन बना कर गैर आदिवासीयों को बेच दिया गया है। हमारे किसी भी पूर्वज ने उक्त प्लॉट पर जमीन नहीं बेचा है। बेचेंगे भी तो आदिवासी के पास ही, और आदिवासी के नाम के बाला और दाखिल खारिज होना ही अपराध है। इसकी कानूनी तरीके से जांच पड़ाताल करवाने की मांग करता है। दोषी पाए जाने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे उत्तरोक्त मामले के बाबत अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ने कहा है कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है। भू-माफिया और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी बना कर सन 1993 के आस पास ही गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यहां भू-माफियाओं और कार्यालय कर्मियों के गठजोड़ से जमीन को गैर आदिवासी को बिना परमिशन पूर्वज रतिया उरांव, भुट्टा उरांव, दूम्ह उरांव वैष्णव के साथ छेड़छाड़ कर कहाँ रकवा को घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कहाँ आदिवासी जमीन को ही गैर आदिवासी बना कर गैर आदिवासीयों के नाम दाखिल खारिज कर उनके नाम रसीद भी जारी कर दिया जा रहा है।

यह





## एक नजद इधर गी

## भारत के समृद्धशालियों व प्रतिभाओं का पलायन क्यों?

**धनाद्य परिवारों का भारत से पलायन कर विदेशों में बसने का सिलसिला चिन्ताजनक है।** ऐसे क्या कारण है कि लोगों को देश की बजाय विदेश की धरती रहने, जीने, व्यापार करने, शिक्षा एवं रोजगार के लिये अधिक सुविधाजनक लगती है, नये बनते भारत के लिये यह चिन्तन-मंथन का कारण बनना चाहिए। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित 6,500 हाई-नेट-वर्थ ईडीविजुअल्स (एचएनआई) के 2023 में भारत से बाहर जाने की संभावना है, पिछले वर्ष की तुलना में यह करोड़पतियों के देश छोड़कर जाने की 7500 की संख्या भले ही कुछ सुधरी है, लेकिन नये बनते, सशक्त होते एवं आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भारत के लिये यह चिन्तन का विषय होना ही चाहिए कि किस तरह भारत की समृद्धि एवं भारत की प्रतिभाएं भारत में ही रहे। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च निवल मूल्य वाली व्यक्तिगत आबादी के 2031 तक 80 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है, जो इस अवधि के दौरान भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते धन बाजारों में से एक के रूप में स्थापित करता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से देश के भीतर संपन्न वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों द्वारा संचालित होगी। इसमें समृद्ध व्यक्तियों के भारत लौटने की प्रवृत्ति को भी देखा जा रहा है, और जैसे-जैसे जीवन स्तर में सुधार जारी है, यह अधिक संख्या में धनवान व्यक्तियों के भारत वापस आने का अनुमान लगाता है। लेकिन प्रश्न है कि भारत के करोड़पति आखिर नये बनते भारत एवं उसकी चिकित्सा, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक उज्ज्वलता के बावजूद क्यों विदेश जा रहे हैं? वैसे तो यह हर किसी का व्यक्तिगत अधिकार और चाहत हो सकती है कि वह कहाँ बसना और कैसी जीवनशैली चाहता है? लेकिन हाई नेटवर्थ वाले (अति समृद्ध) हमारे देशवासियों के देश छोड़ कर कहाँ और बसने की तैयारी की ताजा रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है।

दुनियाभर में धन और निवेश प्रवासन के रुक्खान को टैक करने वाली कंपनी की सालाना रिपोर्ट में अति समृद्ध भारतीयों का अपना सब-कुछ समेट कर हमेशा के लिए भारत से जुदा हो जाने का अनुमान अनेक प्रश्न खड़े करता है, सरकार को इन प्रश्नों पर गौर करने की जरूरत है। संतोष इस बात पर किया जा सकता है कि ऐसा कदम उठाने वाले इन अति समृद्धशालियों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग एक हजार कम है। लेकिन यह संख्या समृद्ध विश्व में सर्वाधिक है। भारत के दृष्टिकोण से इस तथ्य का विश्लेषण ज्यादा जरूरी हो जाता है। जानना यह भी जरूरी है कि बचपन से जवानी तक का एक-एक पल देश में जुगाने और यहीं अमीर बनने का सफर तय करने के बाद देश से मोह भग होने के कारण आखिर क्या हो सकते हैं? उम्मीद यह की जाती है कि देश में रहकर समृद्ध हासिल करने वाले समय आने पर देश को लौटायें भी। सवाल यही है कि देश को लौटाने और फायदा देने का वक्त आता है तब एकाएक विदेश में जाकर बसने की ललक कैसे और क्यों पैदा हो रही है? अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के समय इस तरह की पलायनवादी सोच का उभरना व्यक्तिगत स्वार्थ, सुविधा एवं संकीर्णता को दर्शाता है। बड़ा सवाल यह भी उठाना स्वाभाविक है कि आखिर क्या कमी है हमारे यहाँ? यह बात सही है कि गांव से कस्बे, कस्बे से शहर और शहरों से महानगरों में जाकर बसने की मानवीय प्रवृत्ति होती है। इसे विकास से भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन जब यह दौड़ बहुत ज्यादा होने लगे और लोग अपनी जड़ें ही छोड़ने को आकुल दिखें तो सोचना जरूरी हो जाता है। मुर्बई, दिल्ली, बैंगलूरु जैसे महानगर दुनिया के दूसरे महानगरों को टक्कर देने वाले हैं। फिर भी अगर ये भारतीय विदेशी महानगरों को ही चुन रहे हैं, तो तमाम पहलुओं पर विचार भी करना होगा। यह इसलिए भी जरूरी है कि यह दौड़ भारतीय महानगरों से विदेशी महानगरों की तरफ ही है।

■ ललित गर्ग

# बराक ओबामा भारत को सुरक्षा की सीख न दें

**देखा** जाये तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस साक्षात्कार की टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठे ही हैं साथ ही इसके जरिये वह टूलिकिट भी सामने आ गयी है जिसके जरिये मोदी को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे को लेकर निशाने पर लेने का प्रयास किया जाता है। अमेरिका के राजकीय दौरे पर यह ग्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जब राष्ट्रपति जो बाइडन तथा उनका पूरा प्रशासन पलक पांवड़े बिछा रहा था उसी समय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीएनएन को दिये एक साक्षात्कार के जरिये सनसनी फैला दी। इस साक्षात्कार में उन्होंने भारत के मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताई। साक्षात्कार में ओबामा ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करता तो मैं उनसे कहता कि अगर वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तो भारत के टूटने की संभावना बनी रहेगी। ओबामा ने राष्ट्रपति जो बाइडन को भी सलाह दी कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उनसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करें। देखा जाये तो ओबामा के इस साक्षात्कार की टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठे ही हैं साथ ही इसके जरिये वह टूलिकिट भी सामने आ गयी है जिसके जरिये मोदी को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे को लेकर निशाने पर लेने का प्रयास किया जाता है। विदेशी मीडिया का इस संबंध में खूब सहारा लिया जाता है। बीबीसी गुजरात दंगों के 20 साल बाद उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जनरल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को भारत में हो रहे विकास या मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछने की बजाय सिर्फ अल्पसंख्यकों की चिंता सताती है। आप जरा सभी घटनाओं को जोड़ कर देखेंगे तो आपको सारी कढ़ियां जुड़ी हुई नजर आयेंगी। भारतीय प्रधानमंत्री की घेराबंदी करने के लिए धर्म का धंधा करने वाले टूलिकिट से जुड़े लोगों ने मोदी के अमेरिका आगमन से पहले कुछ भारत विरोधी अमेरिकी सांसदों से एक पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखवाया और उनसे मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। भारत विरोधी कुछ अमेरिकी सांसदों ने मोदी के स्वागत समारोह और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मोदी के संबोधन का बहिष्कार भी किया। यह लोग मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर पोस्ट भी करते रहे ताकि मोदी विरोधी अधियान को गति मिलती रहे। इसके अलावा, एक ओर उमर खालिद को रिहा करने की मांग संबंधी पोस्टर अमेरिका में लहराये गये तो दूसरी ओर खालिस्तान समर्थकों ने भी भारत विरोधी नारे लगाये। इस बीच, सबके सुर से सुर मिलते हुए बराक ओबामा ने सीएनएन को साक्षात्कार देकर माहौल गमाने का प्रयास कर अपना भी योगदान दे दिया। देखा जाये तो बराक हुसैन ओबामा के मन में मोदी विरोधी भावना आज से नहीं बल्कि शुरू से ही है। ओबामा को 2014 में यह कर्ताई नहीं भाव्या था कि आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की इतनी प्रचंड विजय हुई कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद से सीधे मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गये। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबामा पश्चासन इस बात के लिए मजबूर हो गया।

स्वामी, परिजात माइनिंग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि. की ओर से इसके पब्लिकेशन डिवीजन, रेडमा मेदिनीनगर, पेट्रोल पम्प, रातू, रांची-835222, झारखण्ड द्वारा मुद्रित रजिस्ट्रेशन नं. **RNI. 61316/94** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. पलामू-822102, फोन नम्बर : 07759972937, 06562-240042/ 222539, फैक्स नम्बर : 06562-2283386. दिल्ली कार्यालय : 25-एलएफ. तानसन मार्ग, नई दिल्ली-1, गढ़वा कार्यालय : मेन सोड, गढ़वा-8.

# आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह ग्रासदी

भारत में संविधान का शासन है संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में खुबसूरत अधिकार विभाजन किये हैं लेकिन आपातकाल आधुनिक इतिहास में संविधान को तहस-नहस करने की भयावह त्रासदी है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज से 48 वर्ष पूर्व (25 जून 1975) पूरे देश को कैदखान बना दिया था। संविधान (अनुच्छेद 352) में वाद्य आक्रमणों और देश के भीतर गंभीर आतंरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित करने की व्यवस्था थी। लेकिन तब देश में कोई आतंरिक अशांति नहीं थी प्रधानमंत्री स्वयं आतंरिक अशांति से पीड़ित थीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को उनका संसदीय चुनाव अवैध घोषित कर दिया था न्यायालय के अनुसार वे अनुचित साधनों द्वारा चुनाव जीती थीं रायबरेली (उत्तर प्रदेश) की उनकी संसदीय सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। सत्ता पक्ष का एक धड़ा और संपूर्ण विपक्ष त्यागपत्र मांग रहा था। उन्होंने पद से न हटने का निश्चय किया आपातकालीन प्राविधान का दुरुप्योग किया और आपातकाल थोप दिया संविधान के रास्ते तानाशाही थोपने के ऐसा ही कृत्य एडोल्फ हिटलर ने 28 फरवरी 1933 को जर्मनी में किया था हिटलर जर्मनी के चांसलर (सत्

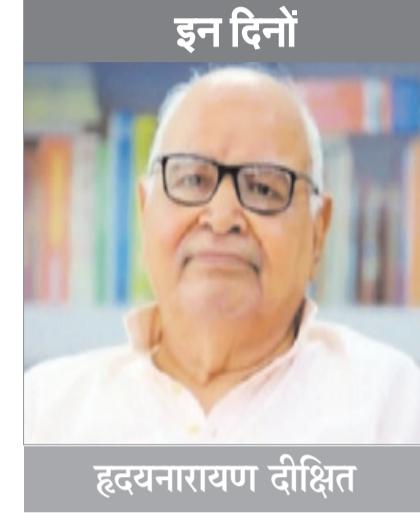
प्रमुख) थे। आपातकाल पर जर्मनी की संसद में मतदान हुआ। संसद का बहुमत हिटलर के पक्ष में था। 444 मत आपातकाल के पक्ष में पड़े। विपक्ष में 94 वोट पड़े। 109 लोगों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह भारत में भी सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री के पक्ष में था। जान पड़ता है कि श्रीमती गांधी हिटलर से प्रेरित थीं। यहां पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था। जर्मनी की तर्ज पर यहां कांग्रेस संसदीय दल और पार्टी ने इस तानाशाही का समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा को इंडिया बताया और इंडिया को इंदिरा। स्वाधीनता आंदोलन के महान नेता जयप्रकाश नारायण को भी गिरफतार किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सहित सभी राष्ट्रवादी नेता भी जेल में थे। मानवता कुचली गई। पुलिस अंग्रेजी शासन की पुलिस की भूमिका में थी। विचार अभिव्यक्ति का गला घोट दिया गया। प्रतिष्ठित पत्रकार पीड़ित किये गये। प्रधानमंत्री न्यायालयों की शक्ति पर आक्रामक थीं। श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की। संविधान में हास्यास्पद संशोधन हुआ। प्रधानमंत्री के संसदीय चुनाव को न्यायालिक निर्वचन से मुक्त कराने का संशोधन कराया गया और इस संविधान संसोधन को पिछली तारीखों से लागू कराया गया। आपातकाल का बयालिसवां संशोधन ध्यान देने योग्य है। संविधान में संसदीय अधिनियम पर भी न्यायालिक पुनर्निर्विलोकन की व्यवस्था है। लेकिन आपातकाल में संविधान के उल्लंघन के आधार पर चुनावी देने के लिए संघ और राज्यों के कानूनों में भेद किया गया। यह

रायबरेली की उनकी  
घोषित कर दी गई थी। सं  
और संपूर्ण विपक्ष त्यागपत्र  
पद से न हटने का निश्चय  
प्राविधान का दुरुपयोग कि  
थोप दिया। संविधान के रा  
का ऐसा ही कृत्य एडो  
फरवरी 1933 को जम

व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायपीठ  
अनुच्छेद 32 के अधीन अपनी  
अधिकारिता में किसी राज्य के कानूनों  
को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं  
कर सकता जब तक ऐसी कार्यवाहियों  
में केन्द्रीय विधि भी प्रश्नवाचक न हो।  
व्यवस्था की गई कि नीति निदेशक

तत्वों को लागू करने के लिए अधिनियमित कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जायेगी। इसी तरह उच्च न्यायालयों को केन्द्रीय विधि की असंवैधानिकता के विरुद्ध सुनवाई से रोक दिया गया। किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए न्यायमूर्तियों के विशेष है। आपातकाल में संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 का भी संशोधन किया गया। व्यवस्था की गई कि संविधान संशोधन विधि के नाम से घोषित विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अकारण जेल भेजा गया। लाखों कार्यकर्ता जेल

(मीसा) में नैसर्गिक कानून का यह सूत्र नहीं था। मीसा में जिला प्रशासन द्वारा व्यक्ति को उठाकर जेल भेज दिया जाता था। न्यायालय में उसका मुकदमा नहीं चलता था। ऐसा कानून दुनिया के किसी भी सभ्य देश में नहीं है। लेकिन भारत में पुलिस राज था। पुलिस अनावश्यक रूप से पीटीरी थी। हजारों सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंग भंग किये गये। संविधान संशोधनों की झड़ी लग गई। 53 अनुच्छेद एक साथ बदले गये। सातवीं अनुसूची बदली गई। प्रेस का मुंह कुचल दिया गया था। सब तरफ उत्तीर्ण व सरकार प्रायोजित हिंसा का चीत्कार था। मौलिक अधिकार भारत की संवैधानिक व्यवस्था के प्राण हैं। वे स्थापित सरकार के अत्याचारों से रक्षा करने के उपकरण हैं। राज व्यवस्था की निररुक्षता से संरक्षण देने के लिए मौलिक अधिकार अधिनियमित किये गये थे। श्रीमती इंदिरा गांधी मौलिक अधिकारों में भी काट छाट कर रहीं थीं। संविधान (भाग 4) में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के बहाने बनाई गई विधियों को न्यायालिक निर्वचन से अलग रख दिया गया था। सरकारी अत्याचारों से देश उबल रहा था। मुझे मीसा बंदी के रूप में उत्पीड़न का अनुभव है। उस समय लागू डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल (डीआईआर) का भी अनुभव है।



इन दिनों

हृदयनारायण दीक्षित

रायबरेली की उनकी संसदीय सीट रिक्त  
घोषित कर दी गई थी। सत्ता पक्ष का एक धड़ा  
और संपूर्ण विपक्ष त्यागपत्र मांग रहा था। उन्होंने  
पद से न हटने का निश्चय किया। आपातकालीन  
प्राविधान का दुरुपयोग किया और आपातकाल  
थोप दिया। संविधान के रास्ते तानाशाही थोपने  
का ऐसा ही कृत्य एडोल्फ हिटलर ने 28  
फरवरी 1933 को जर्मनी में किया था।

1

# लोकतंत्र पर जबरदस्त आघात

सत्ता का ताकत का दुरुपयोग कंस किया जाता है, इसका उदाहरण कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में देश पर तानाशाही पूर्वक लगाया गया आपातकाल है। जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार ही समाप्त कर दिया था। इसे एक प्रकार से देश की आजादी को छीनने का दुस्साहसिक प्रयास भी माना जा सकता है। क्योंकि इंदिरा शासन द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल में सरकार के विरोध में आवाज उठाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। यहां तक कि सरकार ने विषय की राजनीति करने वालों के साथ ही उन समाजसेवियों और राष्ट्रीय विचार के प्रति समर्पित उन संस्थाओं के व्यक्तियों को जेल में ठंस दिया था, जो सरकार की कमियों के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे थे। सरकार के इस कदम को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंदिरा गांधी की सरकार ने अपनी सरकार के खिलाफ उठाने वाली हर उस अवाज को दबाने का प्रयास किया, जो लोकतांत्रिक रूप से भी सही थी। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस शासन का यही चरित्र रहा है कि उनके खिलाफ उठाने वाली आवाज को किसी भी प्रकार से शांत किया जाय। आज भी कांग्रेस ठीक इसी पद्धति से काम करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बलि दी जाती रही है। इसे कांग्रेस का स्वभाव ही माना जा सकता है कि उसने देश को मजबूत करने वाली आवाज को मुखर नहीं होने दिया। इसके विपरीत देश के विरोध में उठाने वाली आवाज को बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की आजादी कहकर समर्थन किया। सीधे शब्दों में निरुपित किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस को अपने विरोध में कही गई कोई बात जरा भी पसंद नहीं है। इसी कारण नेशनल हेराल्ड में जब जांच की बात आती है तो कांग्रेस के नेता एक जुट होकर ऐसा प्रदर्शन करते हैं, जैसे वही सही हैं और बाकी सभी गलत। कांग्रेस पार्टी ने

एक नहा कड़वा बार आभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्रपति विरोधी ताकतों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का काम किया है, लेकिन जो कांग्रेस गाहे बगाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बकालत करती रही है, उसने ही 25 और 26 जून 1975 की रात को आपातकाल लगाने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह गला घोट दिया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस प्रकार कुठाराधात किया जाता है, इस तथ्य को जानने के लिए कांग्रेस के नेताओं को आपातकाल के काले अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। आपातकाल के नाम पर कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी भयंकर यातानाएं देते हुए देश भक्तों पर कहर बरपाया। जिसके स्परण मात्र से दिल में सिरहन दौड़ जाती है। जिन लोगों ने इस काली रात का साक्षात्कार किया, उनके अनुभव सुनने मात्र से ही लगता है कि इन्होंने आपातकाल को किस कदर भोगा होगा। आपातकाल लगाने के पीछे के कारणों पर व्यष्टिपात किया जाए तो यही तथ्य सामने आते हैं कि उसके समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरी तरह से तानाशाह शासक की भूमिका में दिखाई दीं। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा बताते हुए अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, यह प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही था। वह निर्णय क्या था? इसकी जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनारायण को पराजित किया था, लेकिन चुनाव का परिणाम आने के चार साल बाद राज नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर छह साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगाया दिया और उनके मुकाबले हारे और श्रीमती गांधी के विराट प्रतिद्वंद्वी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर

दिया था। राजनारायण सिंह का दलाल था कि इंदरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तथ सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। न्यायालय ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया और देश में आपातकाल घोषित कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ ही गुजरात में चिमनभाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदरा गांधी बौखला गई। इन्दिरा गांधी ने न्यायालय के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी का यह कदम न्यायालय के आदेश का अपमान करने वाला ही था। आपातकाल के नाम पर केवल उन्हीं लोगों को जेत में जबरदस्ती बंद किया था, जो सरकार के विरोधी थे। देश भर में इंदिरा शासन के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। आपातकाल में शासन, प्रशासन ने लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हर उस व्यक्ति को प्रताड़ना दी, जो लोकतांत्रिक तरीके सरकार के विरोध में आवाज उठा रहे थे। विपक्षी राजनेताओं ने देश में केन्द्र सरकार के विरोध में ऐसा वातावरण बनाया कि इंदिरा गांधी को अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखाई दिया। जॉर्ज फन्नीडीज को लोहे की जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी गई। देश के जितने भी बड़े नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पांछे डाल दिए गए। एक तरह से जेते राजनीतिक पाठशाला बन गई। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा, उनका यही कहना था कि ऐसा दृश्य तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं दिखा।

— शुश्रावस्तुपाणी

है ज विचित्र बात !

## प्राण का तकिया कलाम व गेटअप

अपने किरदारों का यादगार तथा फिल्म इंडस्ट्री में लब समय तक अपनी मांग और लोकप्रियता बनाए रखने के लिए प्राण ने अपने मेकअप ( रूप सज्जा ), गेटअप ( वस्त्र सज्जा ) और बोलने के ढंग ( लहजे ) पर विशेष मेहनत तो की ही, यह भी ध्यान रखा कि इनमें दोहराव न हो। इन सब की प्रेरणा वे अपने आसपास के लोगों से लेते या पत्र-पत्रिकाओं में छपी तस्वीरों और उसके विवरण से। बोलने के खास लहजे या 'तकिया कलाम' की बात करें तो फिल्म 'पत्थर के सनम' ( 1960 ) में उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया तकिया कलाम था- क्यों? ठीक है ना ठीक ?' यह तकिया कलाम उन्होंने लाहौर में फिल्में करते समय रूप के शैरी के मामाजी से लिया था जो उनके स्टूडियो की देखभाल किया करते थे। फिल्म दस लाख ( 1966 ) में उन्होंने अपनी हर बात को दुबारा गलत अंग्रेजी में बोलकर हास्य का पुट भरा तो फिल्म 'कश्मीर की कली' ( 1964 ) में 'स' को श बोलकर - 'शताले, शताले शम्पा कभी तो मेरा शम्य भी आएगा' ने भी दर्शकों को खूब हँसाया। फिल्म कसौटी ( 1974 ) में की गई नेपाली गोरखे की भूमिका में नेपाली लहजे में बोला गया तकिया कलाम हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है भी काफी लोकप्रिय हुआ था। अपनी खलनायकी को खुंखार और डरावना बनाने के लिए उन्होंने कई फिल्मों में सिगरेट या चीड़ी पीने तथा पान खाने के अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। फिल्म मर्यादा ( 1971 ) में उन्होंने जलती हुई सिगरेट को जीभ द्वारा मुँह के अंदर ले जाकर जोध या होठ जलाए बिना दौबारा उसी तरह होठों पर लाने का करिश्मा किया ( अमिर बान ने इस

तरीके की नकल फिल्म गुलाम में की)। फिल्म 'दिल तेरा दीवाना' (1962) फिल्म में वह अपने मुहं में दबाई बीड़ी को बोलते समय जीभ के निचले होठ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक धमाते रहते थे। अपनी बेटी के डास टीचर जो कि विकलांग थे और खास तरीके से चलते थे की नकल उन्होंने 'हीर-राजा' (1970) में लंगड़े की भूमिका करते हुए की। फिल्म 'चार के घर चोर' (1978) में एक पागल के किरदार के लिए उन्होंने उस पागल का गेटअप लिया जिसे वे बांद्रा में अवसर देखा करते थे और जो मिलिट्री की पोशाक और उस पर मेडल लगाकर सीटी बजाता रहता था। उनके विग और गेटअप हमेशा कुछ अलग होते थे और दर्शकों को बेहद पसंद आते थे। विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के प्रति विशेष आकर्षण के चलते उन्होंने खानदान (1966) फिल्म में हिटलर की तरह छोटी मूँछे और बाल रखे। अमर अकबर एंथेनी में उनकी दाढ़ी और कपड़े अब्राहम लिंकन जैसे थे। फिल्म ज़ुगनू (1973) में प्रोफेसर की भूमिका के लिए उन्होंने शेष मुजीबुरहमान जैसा मेकअप और गेटअप किया था। यानी उन्हीं के जैसी कुर्ता, विग, मोटे फ्रेम का चश्मा और मूँछे। बाद की फिल्मों निगाहें (1989) में उन्होंने सैम पितोदा की तरह दाढ़ी और फिल्म जोशीले (1973) में शशि कपूर के ससुर ज्योकी कैंडल की तरह दाढ़ी रखी। वेशभूषा की सत्यता के लिए प्राण जिस धर्म का किरदार निभा रहे होते तो उसी सम्पुदाय के किसी भी व्यक्ति से सहयोग लेने में नहीं हिचकते थे। फिल्म 'कसौटी' में उन्होंने एक नेपाली गोरखे की भूमिका के लिए अपने मित्र से गोरखाओं जैसे कपड़े तो मंगाए ही साथ ही उनके द्वारा साथ रखी जाने वाली खुखरी तक मंगाई और उसे शूटिंग में भी ले गए। फिल्म अंसू बन गये फूल (1969) में उन्होंने मोहल्ले के दादा का मराठी किरदार निभाया था। इसके लिए उन्होंने अपने मराठी इलेक्ट्रिशियन से कुछ चुने हुए मराठी शब्द याद कर अपने संवादों में शामिल किए। चलते-चलते : जिस देश में गंगा बहती है (1960) फिल्म में प्राण ने एक क्रूर डाकू 'राका' की उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी।

■ तीरज्जु क्या पढ़े

■ अंतर्गत सार्व





## हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जुर्माना राशि को घटाया



नवीन मेल संवाददाता। रांची झारखण्ड हाई कोर्ट के चौफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अव्यक्तता वाली खंडपीठ ने शनिवार को डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कमेटी के सचिव राजेश ए नंदी की ओर से दावर जनहित याचिका की सुनवाई की। खंडपीठ ने तथा छिपाकर जनहित याचिका वाखिल करने पर याचिकाकर्ता राजेश ए नंदी पर लगाए गए एक लाख रुपये की जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये बाक कर दिया है। याचिकाकर्ता को और से कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह सेवानिवृत्त शिक्षक है। इसलिए जुर्माना सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस केस से हटा दिया था। साथ ही उस पर एक लाख रुपये की जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को एडवोकेट एसोसिएशन, झारखण्ड हाई कोर्ट में जमा करनी अवैध रूप से बेचा जा रहा है,

थी। याचिकाकर्ता की ओर से इसकी जांच कराई जाए। सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ट्रस्ट को प्रॉपर्टी चैरिटेबल कार्यों में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन एक कंपनी बन गई थी जिसका नाम डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ट्रस्ट एसोसिएशन था। वर्ष 1960 में इसकी ऐसेट एंड डायरेसी ट्रस्ट एसोसिएशन के द्वारा इसकी संपत्ति को हजारीबाग में लायबिल छाटनागर डायरेसी ट्रस्ट एसोसिएशन मर्ज कर गया था।

## सिकंदर के जादू ने रांची में मचा रहा धूम

रांची। कचहरी रोड स्थित वेंडर मार्केट के चौथे तल्ले पर बने रॉयल हाईट बैंकेट हॉल में जादूगर सिकंदर के शो में खूब भीड़ हो रही है। लोगों को यह शो खूब भा रहा है। शो के दौरान हैरतगीज कारनामे और अज्ञिक के साथ राजौर का खेल बहुत ही साफाई से परोसा जाता है। साथ ही शो के दौरान सामाजिक जागरूकता भी फैलायी जा रही है। शो में जादूगर सिकंदर लड़की को हवा में उड़ा देते हैं तो उन्होंने आश्रण लागू किये बिना ही पंचायत चुनाव करा दिया गया। उठ बातें सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद साहू ने तीन स्तरीयों को लेकर राजभवन के समक्ष धरने के दौरान कही। राज्य में 77 फैसली सदान निवास करते हैं। सदान बहुल राज्य

## सदान विकास पार्टी ने राजभवन के समक्ष दिया धरना

# ‘हमें हक से वंचित रखने की हो रही साजिश’



### कराटे प्रशिक्षित अपने आप में आत्मविश्वासी होते हैं : विकास

रांची। कराटे प्रशिक्षित उमा हो या अधेड़ अपने आप में आत्मविश्वासी होते हैं। यह बात पतरता के कराटे प्रशिक्षित विकास पाठक ने कही। वे शनिवार को भवानी नगर पिरों के संत ज्युस्स स्कूल औं काठीयांड स्थित ग्लोबल किंडिस स्कूल में कराटे का प्रशिक्षण दे रहे थे। विकास मॉडर्न मार्शल ऑफर्स कराटे डॉ फेडरेशन ऑफ ईंट्रियो सह कराटे फेडरेशन ऑफ शोतोकॉन के तहत स्कूली बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण देना शुरू किया है। संत ज्युस्स स्कूल की प्राचारणी किंग मिश्र ने कहा कि कराटे बच्चों के विकास का एक बेहतरीन जरिया है। इसमें बच्चे आत्मक्षमता सीखते ही हैं साथ ही वे अपने आप में इनसे सक्षम हो जाते हैं। उद्धाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सहित गणमान लोगों को राज्य सभा में आमंत्रण प्रदेशीय वर्दे भारत ट्रेन हैरिया स्टेशन से अपराह्न बाद 3:55 बजे खुलेगी और शहर की ओर प्रदर्शित किया जाएगा। दृष्टिकोण पर्यंत रांची के वरिष्ठ मंडल कार्यक्रम अधिक जवानों को तैनात किया गया

# गोड्डा में कुएं की सफाई के दौरान किशोर की मौत, पांच लोग गंभीर



नवीन मेल संवाददाता। रांची जिले के महागामा अनुमंडल क्षेत्र के पुनर्वासित गांव बड़ा भोंडाई के एक कुएं की सफाई करने के लिए बच्चों के साथ देखा गया था। जिले के बड़ा भोंडाई के एक कुएं में उत्तर वाले गंभीर अपराह्न बाद 3:55 बजे खुलेगी और उसे अपनी आत्मीय होती है। वह बच्चों को अकेला नहीं महसूर करते हैं, जिससे उन्हें डर लगे।

हलचल बंद हो गई। उसे बचाने के लिए उसके पिता मकसूद अंसारी भी कुएं में उतर गए। शोर-शराबा सुनकर वहाँ असापास के कई लोग जमा हो गए। उन दोनों को बचाने के क्रम में पांच अन्य लोग गंभीर अपराह्न बाद 4:10 बजे खाली हो गये। जानकारी के अनुसार गांव का 10 वर्षीय मसूद अंसारी गंदी साकरने के लिए कुएं में उतरा, जहाँ उसकी कारण गंदी लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बालक की मौत कुएं में उत्तरन हो रहे विहली गैस के कारण हो गई एवं उन्होंने जिले के बालकों की मौत की जांच-पढ़ताल कर रही है।

## पृष्ठ एक का शेष

### राज्यपाल ने किया लोक...

उन्होंने कहा कि एक सम्पादनक जिंदगी के लिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी होनी चाहिए। लोक संवाद में स्वयं

सहायता समूह की दीदियों ने भी अनुभव साझा किया। राज्यपाल ने जिले में एक लाख से

अधिक महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही कहा

कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं को कारण योग्य करने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए अवकाश नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बालक की मौत कुएं में उत्तरन हो रहे विहली गैस के कारण हो गई एवं उन्होंने जिले के बालकों की मौत की जांच-पढ़ताल कर रही है।

घरवाले भी इस बात से प्रसन्न हैं। मेरे दादा

गोरखनाथ विश्वासी से राजभवन के स्वाक्षर से

रिटायर हुए हैं। मेरे पिता का नाम प्रमोद

कुमार तिवारी है। यापा सिविल कोर्ट,

पलामू में चपरासी हैं और मां संगीता देवी

गृहणी हैं। मेरी एक छोटी बहन है जो

एम्बेडर के लोगों में एक लोहा देवी

है। मेरी दोस्री पिता का नाम विश्वासी

कुमार है। जिसके पांच लोगों में

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

मिली है। जिसके लिए उन्होंने

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी

